सरकार ने बदली तेल-गैस टैक्स नीति

रॉयल्टी दरों और प्रक्रियाओं को अधिक तर्कसंगत और सरल बना दिया है

नई दिल्ली, 12 मई केंद्र सरकार ने तेल और गैस क्षेत्र से जुड़ा एक बड़ा और अहम फैसला लिया है. सरकार ने कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और केसिंग हेड कंडेनसेट के लिए रॉयल्टी दरों और प्रक्रियाओं को अधिक तर्कसंगत और सरल बना दिया है. इस कदम का उद्देश्य देश के अपस्ट्रीम तेल और गैस सेक्टर को अधिक पारदर्शी, स्पष्ट और निवेश के लिए आकर्षक बनाना है.

सरकार के इस फैसले के बाद अब तेल और गैस निकालने वाली कंपनियों के लिए नियमों में बेहतर स्पष्टता आएगी. पहले कई नियमों में जटिलताएं और अस्पष्टताएं थीं, जिससे कंपनियों को संचालन में कठिनाई का सामना करना पड़ता था. लेकिन नए बदलावों के बाद इन कमियों को दूर किया जाएगा और पूरे सेक्टर में विकास की गति को बढ़ावा मिलेगा.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह भारत के तेल और गैस क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत है. उनके अनुसार, रॉयल्टी दरों का यह संशोधन न केवल नियामक व्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि देश में ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा देगा.

इस सुधार से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि तेल और गैस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को अब ज्यादा स्पष्ट और स्थिर नियम मिलेंगे. इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने में आसानी होगी.

> यह कदम भारत के ऊर्जा क्षेत्र को लंबे समय में मजबूत करेगा. स्पष्ट नियमों और बेहतर रॉयल्टी ढांचे से उत्पादन लागत में भी संतुलन आएगा, जिससे अंततः ऊर्जा क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा. सरकार का लक्ष्य है कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए. इसी दिशा में यह सुधार एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. आने वाले समय में इससे न केवल तेल और गैस उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

रुपया 79 पैसे लुढ़का

मुंबई, 12 मई. अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया सोमवार को 79 पैसे टूटकर 95.28 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। पिछले कारोबारी दिवस पर भारतीय मुद्रा 94.49 रुपये प्रति डॉलर पर रही थी. रुपये पर आज शुरू से ही दबाव रहा.यह 38.50 पैसे गिरकर 94.9750 रुपये प्रति डॉलर पर खुला.बीच कारोबार में यह ऊपर 94.8750 रुपये और नीचे 95.34 रुपये प्रति डॉलर तक गया.अंत में यह 95.28 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में आयी तेजी से भी भारतीय मुद्रा कमजोर हुई है.लंदन का ब्रेंट क्रूड वायदा आज 1.5 प्रतिशत की मजबूती के साथ 103 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया.

ईपीएफओ 3 .0 से पीएफ निकासी आसान

नई दिल्ली, 12 मई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने करोड़ों खाताधारकों के लिए एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. जल्द ही ईपीएफओ 3.0 सिस्टम लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद भविष्य निधि (पीएफ) निकालने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी.

इस नए सिस्टम के लागू होने के बाद कर्मचारियों को अपने पीएफ के पैसे निकालने के लिए लंबी प्रक्रिया या दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

नई व्यवस्था के तहत ईपीएफओ खाताधारक अपने पीएफ फंड को एटीएम और यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों के जरिए भी निकाल सकेंगे. इसका उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और

उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है. अभी तक पीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम या कई दस्तावेजों की जरूरत होती थी, जिससे प्रक्रिया में समय लगता था और कई बार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था. लेकिन ईपीएफओ 3.0 इस सिस्टम को पूरी तरह बदलने जा रहा है.

इस नए मॉडल में पीएफ निकासी को बैंकिंग सिस्टम की तरह सरल बनाया जाएगा. कर्मचारी अपनी जरूरत के अनुसार सीधे यूपीआई या एटीएम से तय सीमा तक पैसा निकाल सकेंगे.

> ईपीएफओ का यह अपग्रेड लगभग 7 .8 करोड़ सदस्यों के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है. डिजिटल इंडिया मिशन के तहत यह कदम वित्तीय प्रणाली को और मजबूत करेगा. सरकार का उद्देश्य है कि पीएफ से जुड़ी सभी सेवाएं पूरी तरह डिजिटल और स्वचालित हों, ताकि कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो. ईपीएफओ 3 .0 आने के बाद पीएफ निकासी प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी और धोखाधड़ी की संभावना भी कम होगी. साथ ही दावे (क्लेम) की प्रक्रिया का समय भी काफी घट जाएगा.

एम्ब्रेयर ने भारत फोर्ज के साथ कच्चे माल की डील की

फोर्ज्ड कलपुर्जों की आपूर्ति के लिए भारत का पहला करार

विकासशील बाजारों में औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ावा देने में भी सहायक

नई दिल्ली, 12 मई. ब्राजील की विमान सेवा कंपनी एम्ब्रेयर ने फोर्ज्ड कच्चे माल की आपूर्ति के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ करार की घोषणा की है. एम्ब्रेयर ने किसी भारतीय आपूर्तिकर्ता के साथ पहली बार फोर्ज्ड कच्चे माल की आपूर्ति के लिए करार किया है.

यह समझौता एम्ब्रेयर की वैश्विक सप्लाई चेन को उच्च गुणवत्ता वाले फोर्ज्ड उत्पादों के साथ समर्थन प्रदान करेगा और कंपनी के आपूर्तिकर्ता आधार को विस्तार और विविधता प्रदान करने की रणनीति को मजबूत करेगा. साथ ही, यह प्रमुख विकासशील बाजारों में औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ावा देने में भी सहायक होगा.

एम्ब्रेयर के कार्यकारी उपाध्यक्ष (वैश्विक खरीद एवं आपूर्ति श्रृंखला) रॉबर्ट शेव्स ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखला के लिए कंपनी भारत को एक बड़ा अवसर मानती है.यह अनुबंध एक अधिक मजबूत और प्रतिस्पर्धी आपूर्ति बनाने की योजनाओं को मजबूत करता है.साथ ही भारतीय विमानन उद्योग के विकास के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है.

बड़े स्तर पर उत्पादन क्षमता विकसित करने में सक्षम बनाएंगे

भारत फोर्ज के उपाध्यक्ष एवं सह-प्रबंध निदेशक अमित बी. कल्याणी ने कहा कि यह तथ्य कि भारत फोर्ज एम्ब्रेयर के लिए फोर्ज्ड कलपुर्जों का पहला भारतीय आपूर्तिकर्ता बना है, हमारे लिए गर्व का क्षण है और यह विमानन व्यवसाय में हमारी विकसित क्षमताओं का प्रमाण है.हम एम्ब्रेयर द्वारा जताये गये विश्वास के लिए उनका धन्यवाद करते हैं.आने वाले वर्षों में हम एम्ब्रेयर के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं. ये अनुबंध हमें महत्वपूर्ण कलपुर्जों के लिए बड़े स्तर पर उत्पादन क्षमता विकसित करने में सक्षम बनाएंगे.

सोना और चांदी की कीमतों में आई तेजी

1,592 रुपए महंगा हुआ सोना

11,620 रुपए उछली चांदी

नई दिल्ली, 12 मई. सोना और चांदी की कीमतों में 12 मई को रिकॉर्ड वृद्धि हुई. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशनके अनुसार, 1 किलो चांदी 11,620 **रुपए बढ़कर** 2,67,820 **रुपए पर पहुंच गई.**

इसी तरह, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,592 रुपए चढ़कर 1,51,954 रुपए पर पहुंच गया.इस साल सोना अब तक 18,755 रुपए और चांदी 37,400 रुपए महंगी हो चुकी है. जनवरी में सोना 1.76 लाख और चांदी 3.86 लाख रुपए तक पहुंच चुकी थी. विशेषज्ञ बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में ईरान-इजराइल संघर्ष के कारण निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने में निवेश कर रहे हैं.डॉलर में गिरावट के कारण ग्लोबल मार्केट में सोने की मांग बढ़ी और घरेलू बाजार में भी कीमतें बढ़ गई हैं.

> भारत में शादी सीजन शुरू होने के कारण ज्वेलर्स की मांग भी तेजी से बढ़ रही है.चांदी में तेजी का कारण इंडस्ट्रियल डिमांड, कम स्टॉक और सोने के महंगे होने का प्रभाव बताया गया है. चांदी का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन और सोलर पैनल निर्माण में बड़े पैमाने पर होता है. स्टॉक कम होने से 'शॉर्ट कवरिंग' भी बढ़ी.भारतीय घरों में सोने की कुल मात्रा अब 34,600 टन हो गई है, जिसकी कीमत लगभग 450 लाख करोड़ रुपए है, जो देश की जीडीपी 370 लाख करोड़ से भी अधिक है.सोना-चांदी की तेजी निवेशकों और आम खरीदारों के लिए सतर्कता की घंटी है.

एसबीआई विदेशी मुद्रा में जुटायेगा दो अरब डॉलर

मुंबई, 12 मई.सार्वजनिक क्षेत्र के देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने विदेशी मुद्रा में दो अरब डॉलर जुटाने की दीर्घकालीन योजना बनायी है जिसे बैंक के निदेशकमंडल की मंजूरी मिल गयी है.

एसबीआई ने मंगलवार को शेयर बाजारों को बताया कि निदेशक मंडल की मंगलवार को हुई बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। यह पूंजी दीर्घकालिक पब्लिक ऑफर, निश्चित या फ्लोटिंग दर वाले बॉन्ड के प्राइवेट प्लेसमेंट आदि के माध्यम से जुटायी जायेगी. प्रस्ताव में कहा गया है कि दो अरब डॉलर की यह पूंजी एक ही बार में या कई किस्तों में भी जुटायी जा सकती है.

10 लाख आय पर बंद होगी सब्सिडी

नई दिल्ली, 12 मई एलपीजी सब्सिडी को लेकर सरकार और तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने नियमों को और सख्त कर दिया है. अब उन उपभोक्ताओं की पहचान की जा रही है, जो निर्धारित आय सीमा से अधिक कमाई करने के बावजूद एलपीजी सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं. सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि सब्सिडी का लाभ केवल जरूरतमंद और पात्र परिवारों तक ही पहुंचे.

नियमों के अनुसार, जिन परिवारों की सालाना आय 10 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें एलपीजी सब्सिडी के दायरे से बाहर रखा गया है. इसमें पति और पत्नी की संयुक्त आय को शामिल किया जाता है. यदि किसी उपभोक्ता की आय इस सीमा से अधिक पाई जाती है, तो उसकी सब्सिडी तुरंत और स्थायी रूप से बंद की जा सकती है. तेल कंपनियों ने आयकर विभाग के डेटा के आधार पर ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान करना शुरू कर दिया है. कई उपभोक्ताओं को एसएमएस भेजकर सूचित किया जा रहा है कि उनके रिकॉर्ड के अनुसार वे सब्सिडी के पात्र नहीं हैं. हालांकि, यदि किसी उपभोक्ता को लगता है कि यह जानकारी गलत है, तो वह 7 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है.

एलपीजी सब्सिडी योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है.

शेयर बाजार में आई गिरावट

मुंबई, 12 मई रुपये पर जारी दबाव और आईटी कंपनियों में भारी बिकवाली के कारण मंगलवार को घरेलू शेयर बाजारों में शुरुआती कारोबार में गिरावट देखी गयी.

बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 326.89 अंक टूटकर 75,688.39 अंक पर खुला. खबर लिखे जाते समय यह 668.47 अंक (0.88 प्रतिशत) की गिरावट के साथ 75,346.81 अंक पर था.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 93.25 अंक टूटकर 23,722.60 अंक पर खुला. खबर लिखे जाते समय यह 179.60 अंक यानी 0.75 प्रतिशत नीचे 23,636.25 अंक पर रहा. अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपये में आज भी गिरावट रही और यह अब तक के ऐतिहासिक निचले स्तर तक लुढ़क गया.

पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में 'पांडुलिपियों का निवारण एवं संरक्षण' विषय पर मंथन

पांडुलिपियाँ भारत की अतुलनीय सभ्यतागत धरोहर

हरिद्वार, 12 मई. भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की प्रमुख पहल 'ज्ञानभारतम् मिशन' के अंतर्गत 'पांडुलिपियों का निवारण एवं संरक्षण' विषय पर पाँच दिवसीय कार्यशाला का आयोजन पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, हरिद्वार में किया जा रहा है.

इस मिशन का उद्देश्य भारत की विशाल एवं अमूल्य पांडुलिपि विरासत का संरक्षण, दस्तावेजीकरण तथा डिजिटलीकरण करना है, ताकि यह प्राचीन ज्ञान-संपदा भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके. कार्यशाला का आयोजन पांडुलिपि संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा संरक्षण एवं भंडारण संबंधी कौशल

विकसित करने के उद्देश्य से किया गया. कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों, विशेषज्ञों तथा विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की.कार्यक्रम का शुभारंभ यज्ञ एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ.अतिथियों का स्वागत शॉल, माला एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर किया गया.स्वागत उद्बोधन पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की अनुसंधान प्रमुख डॉ. वेदप्रिया आर्या ने दिया.पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष डॉ. अनुपम श्रीवास्तव ने 'फ्लोरा' की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंड में पाए जाने वाले पौधों का व्यवस्थित वैज्ञानिक विवरण होता है, जो पुस्तक रूप में प्रकाशित किया जाता है. उन्होंने कहा कि इस प्रकार का वैज्ञानिक दस्तावेज जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

6 दलों का साथ और कांटों भरा ताज!

चेन्नई. तमिलनाडु विधानसभा जीत में बड़ी जीत के बाद टीवीके को सरकार बनाने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है. टीवीके विधानसभा चुनाव में 108 **सीटें जीतने के बाद भी बहुमत साबित नहीं कर पाई. विजय के पास** 107 **विधायक है, क्योंकि उन्होंने दो विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा था.**

बहुमत के लिए उन्हें 10 विधायकों की जरूरत थी. हालांकि, 5 विजयी विधायकों वाली कांग्रेस ने अपना पूरा समर्थन दिया था, लेकिन फिर भी 5 विधायकों की कमी थी. इसके बाद 2-2 विधायकों वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने विजय को समर्थन दिया, लेकिन राज्यपाल इससे भी संतुष्ट नहीं हुए. दो-दो विधायकों वाले विदुधलाई चिरुथिगल काची और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के शनिवार को समर्थन देने की घोषणा के बाद विजय चौथी बार लोकभवन गये. तब जाकर राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया. टीवीके ने रविवार (10, मई) को सुबह 10 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उन्हें 13 मई तक विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना होगा. विजय के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली.

सीएम जोसेफ विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती तमिलनाडु को एक स्थायी सरकार देना है. विभिन्न दलों से मिलकर बनी यह सरकार को स्थायी बनाना विजय के सामने एक बड़ी चुनौती होगी. कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद गठबंधन में तालमेल और सामंजस्य बनाए रखना यह बहुत जरूरी होगा.

मजबूत प्रशासनिक टीम की जरूरत

> सीएम जोसेफ विजय को तमिलनाडु राज्य में एक मजबूत प्रशासनिक टीम बनानी होगी, जो कि राज्य के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में काम करेगी. उन्हें राज्य में रोजगार और आर्थिक स्थिरता लाने के उपाय करने होंगे. तमिलनाडु में डीएमके जैसे मजबूत विपक्ष का सामना करना भी विजय के लिए कठिनाइयों से भरा होगा. अब विजय को फिल्मी स्टार की भूमिका से निकलकर जमीन पर लोगों के सामने काम करना होगा.

निकाय चुनाव में भी दिखेगी भाजपा की यूथ

सोशल मीडिया पर सक्रियता बनेगी टिकट का आधार

भोपाल. मध्य प्रदेश में निकाय चुनावों के लिए भाजपा ने अपने परंपरागत तरीके में बदलाव करते हुए नए चेहरों को प्राथमिकता देने और चुनावी तैयारी करीब एक वर्ष पहले ही शुरू करने का फैसला लिया है. पार्टी का उद्देश्य युवा नेतृत्व और नए चेहरों को मौका देना है ताकि जमीनी स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन किया जा सके.

योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी ने चुनाव से काफी पहले ही खोजबीन और चयन प्रक्रिया शुरू करेगी. 60 वर्ष से अधिक आयु के नेताओं और लगातार तीन बार पार्षद रह चुके लोगों को टिकट दिए जाने की संभावना बेहद कम है.

सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों की सक्रियता, फॉलोअर्स की संख्या और डिजिटल जुड़ाव को चयन का एक महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है. अगले साल 2027 में नगरीय निकाय के चुनाव प्रस्तावित हैं. पिछले चुनाव में 16 नगर निगमों से पांच में कांग्रेस और एक पर आम आदमी पार्टी का महापौर चुना गया था. इसके अतिरिक्त अन्य नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में बीजेपी का वर्चस्व बरकरार रहा था. इन निकायों में अध्यक्ष के चुनाव सीधे जनता के स्थान पर पार्षदों के माध्यम से कराए गए थे. अब सरकार ने फिर व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया है.

फील्ड पर सक्रिय युवाओं को भी मिलेगा मौका

> अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली यानी जनता सीधे मतदान से करेगी. सीटों का आरक्षण भी होगा. इस नई व्यवस्था में भाजपा भी नए चेहरों को अधिक से अधिक अवसर देने की दिशा में काम कर रही है. पार्टी ने तय किया है कि चुनाव से ठीक पहले के बजाय अभी से प्रत्याशी तय करने की दिशा में काम किया जाए. संगठन के फीडबैक के अलावा संभावित प्रत्याशी को लेकर सर्वे भी कराया जाएगा. बीजेपी के संभाग व जिला प्रभारियों की भी जिम्मेदारी तय की गई कि वे अपने-अपने प्रभार के क्षेत्र में ऐसे युवाओं को चिह्नित करें जो पार्टी में सक्रिय और लोकप्रिय हैं. ऐसे युवाओं के नाम आगे बढ़ाए जाएंगे.

विशेष | **कांग्रेस ने इस बार दो जातीय पार्टियों से तालमेल किया था.**

असम में कांग्रेस के सहयोगी नाराज

गोवाहाटी. कांग्रेस पार्टी असम में बहुत बुरी तरह से हारी. उसके सिर्फ 19 विधायक जीते और उसमें भी 18 मुस्लिम हैं. कांग्रेस को लग रहा है कि इससे जो नैरेटिव बन रहा है वह आगे के चुनावों में कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगा. आगे से मुसलमान भी कांग्रेस को वोट देना बंद कर देंगे. उनका वोट मुस्लिम पार्टियों को जाएगा.

उनके सामने बदरूद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ है तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया एमआईएम भी है. अजमल की पार्टी को तो कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में ही छोड़ दिया था. कांग्रेस ने इस बार दो जातीय पार्टियों से तालमेल किया था. वे दोनों भी कांग्रेस से नाराज हैं.

रायजोर दल के नेता अखिल गोगोई ने कांग्रेस से नाराजगी जताई है. इस बार उनकी पार्टी के दो विधायक जीते हैं. अखिल गोगोई ने कहा कि पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा नदारद थे. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस में रणनीति बनाने और फैसला करने वाला कोई नहीं दिख रहा था.

असल में यह कांग्रेस की चिरंतन समस्या है, जो राष्ट्रीय स्तर पर भी है. कांग्रेस के दूसरे सहयोगी असम जातीयता परिषद के नेता लुरिनजोत गोगोई हैं. उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई. बताया जा रहा है कि वे भी कांग्रेस के प्रचार करने और चुनाव लड़ने की शैली से नाराज हैं. लेकिन कांग्रेस पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

कांग्रेस ने गौरव गोगोई को नेता बनाया था. वे विधानसभा का चुनाव हार गए. अब वे दिल्ली की राजनीति करेंगे क्योंकि वे लोकसभा में पार्टी के उप नेता हैं.

इधर कैबिनेट विस्तार उधर बृजभूषण ने बढ़ाई टेंशन!

लखनऊ. यूपी में विधानसभा चुनाव में अब एक साल से भी कम का वक्त बचा है. योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है. इससे पहले बीजेपी सांसद रहे ब्रज भूषण शरण सिंह का एक सोशल मीडिया पोस्ट से सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है.

लंबे समय से चल रहे ब्राह्मण समाज की नाराजगी को देखते हुए भाजपा ने मनोज पांडेय को कैबिनेट में जगह दी है. वहीं, बृजभूषण शरण सिंह ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक शायरी पोस्ट करते हुए लिखा, 'शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है.' अब उनके इस पोस्ट को लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग-अलग मतलब निकाले जा रहे हैं.

ऐसा माना जा रहा है कि ये पोस्ट योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनकी नाराजगी हो सकती है. ऐसी चर्चा है कि बृजभूषण शरण सिंह अपने बेटे प्रतीक सिंह को मंत्रिमंडल में जगह दिलाना चाहते थे. हालांकि उन्होंने कभी सार्वजनिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की, लेकिन सियासी हलके में लंबे समय से ऐसी चर्चाएं चल रही थीं. बता दें कि योगी मंत्रिमंडल विस्तार में जिन आठ नेताओं का नाम सामने आया है. उनमें किसी भी ठाकुर चेहरे को जगह नहीं मिलने की बात कही जी रही है. ऐसे में बृजभूषण का ये पोस्ट उसी नाराजगी से भी जोड़कर देखा जा रहा है.

जातिय समीकरण साधने की कोशिश

भाजपा आगामी चुनाव से पहले इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की रणनीति पर फोकस कर रही है. भाजपा का फोकस ब्राह्मण, जाट, दलित, पासी, वाल्मीकि, लोधी और अति पिछड़े वर्ग के नेताओं को जगह देने पर है. यूपी की योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में कुल आठ मंत्रियों ने शपथ ली है. इनमें छह नए चेहरों को शामिल किया गया है, जबकि दो राज्य मंत्रियों को प्रमोट कर कैबिनेट या स्वतंत्र प्रभार दिया गयै है. इन सियासी हलचल के बीच बृजभूषण शरण सिंह का ये पोस्ट राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि पार्टी की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.